बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 111 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 10 फरवरी 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

यमुना खादर में अवैध निर्माण पर एनजीटी सख्त, एमसीडी-डीडीए समेत कई विभागों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। मजनू का टीला क्षेत्र में यमुना नदी के खादर क्षेत्र में अवैध निर्माण होने के खिलाफ एक स्थानीय नागरिक द्वारा भेजे गए पत्र का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्वत संज्ञान लिया है। एनजीटी ने माना कि पत्र में पर्यावरणीय मानदंडों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। एनजीटी ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम दिल्ली (एमसीडी), संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया। एनजीटी ने जिलाधिकारी को अवैध निर्माण करने वालों को विवरण देने के साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या निर्माण यमुना खादर क्षेत्र में हुआ है।

दिल्ली में बीजेपी सरकार का एक साल पूरा, सीएम रेखा ने शालीमार बाग से की विकास के नए अध्याय की शुरुआत

नई दिल्ली । दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के एक वर्ष पूर्ण होने का दिन केवल एक राजनीतिक पड़ाव नहीं, बल्कि भावनाओं, संघर्ष, विश्वास और सेवा के संकल्प से भरा हुआ क्षण बन गया, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग से विकास कार्यों के नए अध्याय की शुरुआत की. पीतमपुरा स्थित डिस्ट्रिक्ट पार्क में अनेक जनहितकारी परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए उन्होंने क्षेत्रवासियों को संबोधित किया तो शब्दों में उपलब्धियों से अधिक संवेदनाएं और आत्मीयता झलक रही थीं.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया. मुख्यमंत्री ने अपने बचपन की स्मृतियों को याद करते हुए कहा कि त्रिनगर से पीतमपुरा आने वाली एक साधारण बच्ची ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वही गलियां एक दिन उसे दिल्ली की सेवा का सर्वोच्च अवसर देंगी. स्कूल-कॉलेज के दिनों की यादें, बाजारों की चहल-पहल और मोहल्ले का अपनापन. इन सबको याद करते हुए उनका स्वर कई बार भावुक हो उठा. उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र ने उन्हें बचपन, पहचान और संस्कार दिए, उसी क्षेत्र की विधायक और फिर मुख्यमंत्री बनना ईश्वर की विशेष कृपा और जनता के प्रेम का परिणाम है.

संघर्ष, विश्वास और जनादेश की कहानी

उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनावी हार ने कभी उनके कदम नहीं रोके, क्योंकि जनता से उनका रिश्ता पद से नहीं, विश्वास से बना है. वर्ष 2025 में दिल्ली में 27 वर्षों बाद भाजपा की सरकार बनना उन्होंने जनता की आकांक्षाओं की जीत बताया और कहा कि यह जनादेश केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि

विकास की दिशा बदलने का संकल्प है.

शालीमार बाग का विकास रिपोर्ट कार्ड

मुख्यमंत्री ने एक वर्ष का रिपोर्ट कार्ड साझा करते हुए बताया कि केवल शालीमार बाग विधानसभा में लगभग 250 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रारंभ या पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि बड़े स्तर की परियोजनाएं हजारों करोड़ रुपये की हैं. डिस्ट्रिक्ट पार्क का पुनर्विकास, नए गेट, फाउंटेन, टॉयलेट, फुटपाथ और जनसुविधाएं–इन सबको उन्होंने क्षेत्र की गरिमा और लोगों की रोज़मर्रा की खुशियों से जोड़ा.

भविष्य की योजनाएं और भावनात्मक संकल्प

उन्होंने मुनक नहर पर प्रस्तावित लगभग 5000 करोड़ रुपये की एलिवेटेड सड़क, नहर किनारे सौंदर्यीकरण और छठ घाट, आधुनिक ऑडिटोरियम, मॉडल स्कूल, नए कम्युनिटी हॉल, विस्तारित आयुर्वेदिक अस्पताल, उन्नत जच्चा-बच्चा केंद्र और नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं को आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ी ऐतिहासिक पहल बताया. साथ ही सड़कों, नालियों, लाइटों, पार्कों और बाजारों के व्यापक सुधार को हर घर तक पहुंचता विकास करार दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेरणास्रोत बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कार्यशैली और ऊर्जा उन्हें निरंतर सेवा के लिए प्रेरित करती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं से आगे बढ़कर यह जनता के विश्वास, कार्यकर्ताओं के समर्पण और सामूहिक संकल्प की यात्रा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के मजबूत समन्वय और सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था ने राजधानी में बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति दी है. फ्लाईओवर, सड़कों, मेट्रो विस्तार और बड़ी संख्या में चल रहीं इलेक्ट्रिक बसों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली आज आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल भविष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ा रही है. अपने संबोधन के अंतिम क्षणों में मुख्यमंत्री का स्वर गहराई से भावुक हो गया. उन्होंने क्षेत्रवासियों को अपना परिवार बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके लिए शालीमार बाग की पहचान एक बहन, बेटी और पड़ोसी की ही रहेगी. उन्होंने आने वाले दिनों में नई योजनाओं, निरंतर उद्घाटनों और तेज़ विकास की गति का संकल्प दोहराते हुए कहा कि यह यात्रा अभी शुरू हुई है.उन्होंने सभी नागरिकों, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का प्रेम ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और इसी विश्वास के साथ विकसित, संवेदनशील और गौरवशाली दिल्ली के निर्माण का संकल्प निरंतर आगे बढ़ता रहेगा.

भाजपा पर आप का हमला, कहा- सीएम रेखा गुप्ता पहली फर्जीवाड़ा दिवस मना रहीं, चुनाव में पैसे बांटे

नई दिल्ली । दिल्ली में भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। आप के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार अपनी पहली वर्षगांठ को फर्जीवाड़ा दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि एक साल पहले विधानसभा चुनाव में खुलेआम जूते-चप्पल, साड़ियां, सोने की चेन और नकद बांटकर चुनाव लूट लिया गया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि चुनाव के दौरान नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को 1100-1100 रुपये बांटे थे और पांच साल तक हर महीने पैसे देने का वादा किया गया, लेकिन सरकार बनने के बाद किसी को रकम नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस एनजीओ के जरिए यह पैसा बांटा गया, वह चुनाव के बाद गायब हो गई। भारद्वाज ने कांग्रेस पर भी

निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के कथित फर्जीवाड़े से चुनाव जीतने का प्रयोग सबसे पहले दिल्ली में हुआ, लेकिन कांग्रेस चुप रही। उन्होंने आरोप लगाया कि जब यही तरीका महाराष्ट्र और बिहार में अपनाया गया तो कांग्रेस ने विरोध किया, जबकि बंगाल में दोबारा चुप्पी साध ली।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र वहीं तक सीमित है, जहां वह खुद चुनाव लड़ती है। नई दिल्ली विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए भारद्वाज ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव तक आते-आते हजारों वोट काटे गए और नए वोट जोड़ने व हटाने के लिए अर्जियां दी गईं। आप ने भाजपा सरकार के एक साल के कार्यकाल पर कई आरोप गिनाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बदहाल हालात, ध्वस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार हो रही मौतों के बावजूद सरकार सत्ता में एक वर्ष पूरा होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, जो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि टूटी सड़कों, खुले नालों, गड्ढों, प्रदूषण और कूड़े के पहाड़ों से जूझ रही दिल्ली में पिछले एक साल में अलग-अलग हादसों में 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सिर्फ जनवरी में 807 लोग, जिनमें अधिकतर महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं, लापता हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी में हर दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन सरकार को न पीड़ित परिवारों की चिंता है न ही प्रशासनिक जवाबदेही की। उन्होंने जनकपुरी में गड्ढे में गिरने से युवक कमल ध्यानी की मौत पर कहा कि ऐसी खतरनाक परिस्थितियां आज दिल्ली की लगभग हर सड़क और चौराहे पर मौजूद हैं। दिल्ली मेट्रो, जल बोर्ड, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी का खुदाई के बाद गड्ढों को बिना सुरक्षा के खुले छोड़ देना आम बात है। उन्होंने राजधानी के कई इलाकों का हवाला देते हुए कहा कि शांति नगर के पास मुनक नहर पुल की टूटी बाउंड्री, तिलक ब्रिज फ्लाईओवर पर गड्ढा, प्रेस एन्क्लेव रोड पर नाले की खुदाई, संगम विहार शूटिंग रेंज, एनएच-9 की सर्विस रोड, द्वारका मोड़, पालम-डाबरी मोड़ और अन्ना नगर में खुले नाले किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं।

दिल्ली के 15 स्कूलों को उड़ाने की धमकी, ईमेल में संसद के अंदर विस्फोट की भी बात

नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय राजधानी के करीब 15 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले, जिसके बाद भारी सुरक्षा तैनाती की गई और एहतियातन स्कूल परिसरों को खाली कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से आठ धमकियां बाद में अफवाह पाई गईं। धमकी भरे ईमेल में भड़काऊ और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसमें दावा किया गया, दिल्ली खालिस्तान बनेगा। पंजाब खालिस्तान है। अफजल गुरु की याद में। ईमेल में यह भी आरोप लगाया गया कि 13 फरवरी को दोपहर एक बजकर 11 मिनट पर संसद के अंदर विस्फोट होगा। इसके बाद विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाते हुए सुरक्षा अलर्ट तेज कर दिया गया।

दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के अनुसार, सुबह के समय शहर के अलग अलग इलाकों स्थित कई शैक्षणिक संस्थानों से आपात कॉल प्राप्त हुई। इसके बाद फायर टेंडर और बम निरोधक दस्तों को तुरंत मौके पर भेजा गया।

डीएफएस के एक अधिकारी ने कहा, अब तक कुल 15 स्कूलों को बम की धमकी मिलने की सूचना मिली है। फायर सर्विस की टीमें तुरंत परिसर में पहुंचीं और गहन जांच जारी है। इनमें से आठ धमकियां अफवाह पाई गई हैं। धमकी पाने वाले स्कूलों में दिल्ली कैंट स्थित लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल, सादिक नगर का द इंडियन स्कूल, आईएनए और लोधी रोड का डीटीईए स्कूल, रोहिणी का वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल, रोहिणी और शालीमार बाग का सीएम श्री स्कूल, पीतमपुरा का आधारशिला विद्यापीठ, शालीमार बाग का मॉडर्न पब्लिक स्कूल, जसपाल कौर पब्लिक स्कूल शालीमार बाग, न्यू राजेंद्र नगर का मानव स्थली स्कूल, द्वारका के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय और रोहिणी का बाल भारती स्कूल शामिल हैं।

एहतियातन स्कूल परिसरों को खाली करा लिया गया और छात्रों व स्टाफ को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। बम डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड प्रभावित स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ईमेल की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए साइबर टीमों को लगाया गया है, जबकि राजधानी के संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने कहा कि अब तक किसी भी स्कूल परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। तलाशी अभियान जारी है।

शशि थरूर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले- सदन चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोमवार को भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और लोकसभा अध्यक्ष पर संसद चलाने में रुचि न रखने का आरोप लगाया और कहा कि लोकसभा में बार-बार व्यवधान के कारण वे केंद्रीय बजट 2026-27 पर बोलने में असमर्थ रहे। सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए थरूर ने कहा कि वे बजट पर चर्चा में भाग लेने की तैयारी के साथ आए थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने का कोई अवसर नहीं मिला। उन्होंने

कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार और लोकसभा अध्यक्ष सदन चलाने में रुचि नहीं रखते हैं। शशि थरूर ने आगे कहा कि वे दिन में बाद में फिर से बोलने का प्रयास करने के लिए लौटेंगे। थरूर ने कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अनुपस्थिति की ओर भी इशारा किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि स्थगन की आशंका पहले से ही थी।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री सदन में बैठी ही नहीं थीं और आगे कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि सदन स्थगित होगा। संसद के दोनों सदनों में सोमवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा जारी रहने का कार्यक्रम था। यह बजट सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर, थरूर ने कहा कि यह फैसला उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मेरे हाथ में नहीं है; आप इस बारे में हाई कमांड से पूछ सकते हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, संसदीय कार्यवाही को लेकर जारी गतिरोध के बीच, विपक्षी सांसद बजट सत्र के दूसरे भाग में अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बना रहे हैं।

भारत-मलेशिया संबंध नई ऊंचाई पर

भारत-मलेशिया संबंध पारम्परिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण रहे हैं। भारत ने 1957 में फेडरेशन ऑफ मलाया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। दोनों देश राष्ट्रमंडल, आसियान क्षेत्रीय मंच, जी-15, जी-77, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और हिन्द महासागर जैसे विभिन्न मंचों के सदस्य भी हैं। भारत मलेशिया संबंधों को अपनी एक्टईस्ट नीति के मूल तत्व के रूप में देखता है। दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंध एक सहस्राब्दी से भी पुराने हैं जिनकी जड़ें चोल साम्राज्य के दौर तक जुड़ी हुई हैं। चोल शासकों ने ही दक्षिण भारत और मलय प्रायद्वीप के बीच समुद्री व्यापार मार्गों को स्थापित किया था। मलेशिया में लगभग 29 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया में भारतीय प्रवासियों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश मानते हैं। इस समुदाय की भाषा तमिल है। हालांकि वहां तेलुगु, मलयालम, पंजाबी और अन्य भाषाओं के लोग भी आप को मिल जाएंगे। रामायण की कथाएं भी मलेशिया की सांस्कृतिक परम्परा का हिस्सा हैं। जिनका स्थानीय रूपांतरण ''हिकायत सेरी रामा'' में देखने को मिलता है। श्री वीर हनुमान मंदिर और कुछ अन्य धार्मिक स्थल साझा सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। 21वीं सदी में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, डिजिटल तकनीक, शिक्षा, चिकित्सा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाया है। दोनों ही देशों ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाया है और स्पष्ट किया है कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड और समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के क्वालालंपुर पहुंचने पर जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ। वह अपने आप में अभूतपूर्व है। अगस्त 2024 में भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली यात्रा है। पूर्व मलेशियाई प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के शासनकाल में दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। महातिर मोहम्मद ने भारत के नागरिकता कानून और जम्मू-कश्मीर से अनुछेद 370 हटाने का विरोध किया था। इतना ही नहीं उन्होंने भारत के भगौड़े इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक को भी शरण दी थी। दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट का दौर बीत चुका है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मोदी और मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम एक ही कार में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम स्थल पर गए। भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों में हाल के वर्षों में निरंतर प्रगति हुई है। दोनों देश अपने रक्षा और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने, अपनी आर्थिक और इनोवेशन पार्टनरशिप को बढ़ाना तथा नए क्षेत्रों में अपने सहयोग का विस्तार करना चाहते हैं। भारत मलेशिया से मुख्य रूप से खाद्य तेल आयात करता है, विशेष रूप से पाम तेल जो भारत की घरेलू आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। इसके अलावा भारत मलेशिया से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, अर्धचालक से जुड़े पुर्जे, रसायन, पैट्रो रसायन उत्पाद, रबर और लकड़ी से बने सामान भी आयात करता है। प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम में बातचीत के बाद दोनों देशों में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इन समझौतों में सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। दोनों देशों ने व्यापार सहयोग 8.59 बिलियन डॉलर से आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसके अलावा दोनों देश निवेश, स्थानीय मुद्रा में व्यापार, पीपल टू पीपल कनेक्टीविटी, ऊर्जा, कृषि, खाद्य सुरक्षा आदि क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाएंगे। भारत लगातार एक के बाद एक व्यापार समझौते कर रहा है और भारत को नए बाजार मिल रहे हैं। दूसरी ओर भारत मलेशिया को पैट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां, वाहन, इस्पात, रसायन, वस्त्र और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी सेवाएं निर्यात करता है। भारतीय दवा उद्योग मलेशिया में अच्छी पहचान रखता है, क्योंकि भारत की सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां वहां के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह भारतीय तकनीकी कंपनियां मलेशिया के डिजिटल विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार को अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाने के लिए व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा की जा रही है, ताकि भारतीय उद्योगों और मलेशियाई भागीदारों दोनों को समान लाभ मिल सके। मलेशिया से भारत को कच्चे माल और रणनीतिक आपूर्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में मलेशिया की वैश्विक भूमिका भारत के लिए खास मायने रखती है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया आपूर्ति श्रृंखला को विविध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं मलेशिया के लिए भारत एक विशाल बाजार, तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और निवेश के असीम अवसरों वाला देश है। भारत की जनसंख्या, डिजिटल और निर्माण क्षमता मलेशियाई कंपनियों को आकर्षित करती है। रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो मलेशिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मलक्का जल डमरू मध्य विश्व के समुद्री मार्गों में से एक है। जहां से वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत का हिन्द प्रशांत विज़न और मलेशिया का दृष्टिकोण एक समान है, जोएक-दूसरे के पूरक है। समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों देशों में नौसैनिक सहयोग बना हुआ है। महातिर के शासन में मलेशिया पूरी तरह से चीन की गोद में बैठा था। अब उसने भी भारत के महत्व को पहचाना है। दोनों देश दक्षिणी चीन सागर और हिन्द महासागर में मुक्त नेवीगेशन और सुरक्षा सहयोग के समर्थक हैं। भारत का डिजिटल भुगतान तंत्र अब दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। अब मलेशिया में यूपीआई के माध्यम से भी लेन-देन होने लगेगा। मलेशिया भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का गेटवे है। भारत अब बड़ी आर्थिक शक्ति है। ताजा समझौते से दोनों देशों के संबंधों को नई गति प्रदान करेंगे।

सैन्य-पुस्तक पर विवादों का बवंडर

तो क्या यह मान लिया जाए सेना के भूतपूर्व अधिकारी अवकाश प्राप्त के बाद केवल गोल्फ-क्लब या 'मिल्ट्री लिटरेचर फेस्टीवल' तक ही सीमित रहेंगे? ऐसा नहीं है लेकिन अवकाश प्राप्त सेना-अधिकारी भी संयम व गरिमा बनाए रखें तो उन्हें ही बेहतर प्रतिष्ठा मिलेगी। हाल ही में पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल रहमान-नरवणे की एक प्रकाशनाधीन पुस्तक 'फोर स्टार्स डेस्टिनी के प्रकाशन पर प्रतिरक्षा मंत्रालय ने फिलहाल रोक लगा रखी है। प्रतिरक्षा मंत्रालय गत एक वर्ष से इस पुस्तक की समीक्षा कर रहा है। कुछेक वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, ऐसी पुस्तकों में यदि कुछ संवेदनशील सामग्री है तो उसकी जांच के बिना उसे प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। यह पुस्तक वस्तुतः आत्मकथा है मगर जनरल नरवणे, जिस सर्वोच्च सैनिक पद पर रहे हैं, जाहिर है उस पद पर रहते हुए अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके सामने से गुजरे होंगे। ऐसा नहीं कि उक्त प्रकाशनाधीन पुस्तक पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन प्रकाशन के पूर्व ही प्रतिपक्षी नेता राहुल गांधी ने सदन में पुस्तक के कुछ अंशों को लेकर हंगामा खड़ा किया, वह भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इससे पूर्व भी अवकाश प्राप्त सेनानायकों की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और विवादों के केंद्र में भी रही हैं। ऐसी ही कृति एक अवकाश प्राप्त मेजर जनरल वीके सिंह की एक कृति 'इंडियाज एक्सटर्नल- सीक्रेट्स आफ रिसर्च एंड एनेलिसिस वर्ष 2007 में प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक को लेकर जनरल वीके सिंह के विरुद्ध सीबीआई ने 'सरकारी गुप्त सूचना-कानून (ओएसए) के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। मेजर जनरल वर्ष 2004 तक चार वर्ष की अवधि के लिए 'रॉ में कार्यरत भी रहे थे। उनकी इस पुस्तक में अनेक ऐसे गुप्त दस्तावेज़ों की भी चर्चा है जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। जनरल के गुरुग्राम स्थित आवास से सीबीआई ने अनेक 'गुप्त दस्तावेज भी बरामद किए और उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया। यद्यपि अधिकृत रूप में अभी कुछ भी नहीं कहा गया है लेकिन सामान्य रूप में यही माना जाता है कि अनेक संवेदनशील एवं अति महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले सैन्य-अधिकारियों को अवकाश प्राप्ति के बाद भी राष्ट्रपति से जुड़ी सामग्री को सार्वजनिक करने से परहेज रखना चाहिए। मेजर जनरल वीके सिंह (रिटायर्ड) की पुस्तक का विवाद अभी भी निपटा नहीं है, जबकि यह सर्वविदित है कि 'सेना-सेवा नियम-1954 की धारा 21 के अनुसार, सेना में सेवारत अधिकारियों पर बिना सरकारी अनुमति कुछ भी सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध है लेकिन रिटायर्ड अधिकारियों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है मगर विशेषज्ञों का कहना है कि कुछेक नियम, परम्परा व सैन्य-सभ्याचार से भी जुड़े होते हैं, इसलिए सेवारत रहते हुए या रिटायर होने के बाद भी कुछ आचार संहिताओं का पालन कर लेना चाहिए। सैन्य सेवा के साथ अक्सर राष्ट्र के अनेक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मामले जुड़े होते हैं, उन्हें सामान्य या सतही रूप में सार्वजनिक करना भी राष्ट्र-हित में नहीं होगा। इसी शृंखला में कुछ अन्य प्रकाशनों पर भी पुनर्विचार का क्रम जारी है लेकिन 'विवादास्पद अथवा संवेदनशील सामग्री को सार्वजनिक करने की छूट पर अभी भी बहस जारी है। यद्यपि विवादास्पद सामग्रियां प्रकाशन से पूर्व ही सार्वजनिक हो जाती हैं और उनका सियासी उपयोग करने का लोभ संवरण कुछ राजनेता नहीं कर पाते। उनके लिए ऐसी सामग्री राजनीतिज्ञों के लिए एक हथियार बन जाती है, मगर उन्हें भी यह सोचना होगा कि राष्ट्र-हित दलगत हितों से कहीं ऊपर होता है। ऐसी सनसनी के आधार पर सिर्फ दो-चार दिन खबरें छपती हैं, मगर इससे राजनेताओं को भी कोई दूरगामी लाभ नहीं पहुंच पाता। अतीत में 'जीप-स्कैंडल, 'ताबूत स्कैंडल आदि अनेक विवाद भी उछले, मगर उनका कोई स्थायी प्रभाव दिखाई नहीं दिया। बेहतर है सत्तापक्ष व प्रतिपक्ष, दोनों ही राष्ट्र-हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारियों को यह भी शायद स्मरण रहता होगा कि उन्हें अन्य वीर जवानों के लिए कैंटीन व्यवस्था व चिकित्सा सुविधाएं सेवानिवृत्ति के बाद भी सम्मान के रूप में जारी रहती हैं। अब तो उसी सम्मान के मद्देनजर 'दिल्ली-कैंट व कुछ अन्य स्थलों के नाम भी वीर जवानों की स्मृति को ही समर्पित कर दिए गए हैं। दुर्गम स्थलों पर उनके लिए हर सम्भव सुविधाएं जुटाना भी हमारा राष्ट्र अपना दायित्व समझता है। यह सब एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सेवा व समर्पण के प्रतीक हैं। इनके अतिरिक्त भी समय पूर्व अवकाश प्राप्ति के बाद उन्हें बैंकों व अन्य सार्वजनिक संस्थानों में भी प्राथमिकता के आधार पर सेवा-अवसर मिल जाते हैं। सेना के एक प्रवक्ता के अनुसार, भारतीय सेना ने 246 सड़कों के नामों से पूर्ववर्ती बर्तानवी सरकारों द्वारा दिए गए नाम बदल दिए हैं। अम्बाला छावनी में पैटर्सन रोड क्वार्टर्ज का नाम 'धनसिंह थापा-एन्क्लेव रख दिया गया है। दिल्ली छावनी में एक सड़क का नाम करूणा खेत्रपाल मार्ग रखा गया है। मथुरा छावनी में एक सड़क का नाम 'अब्दुल हमीद लाइन्स रखा गया है। कुल मिलाकर 124 सड़कों के नाम वीर जवानों की स्मृतियों को समर्पित किए गए हैं जबकि 77 सैन्य-आवास कॉलोनियों के नाम भी दिवंगत सेनानायकों की स्मृतियों को समर्पित किए गए हैं जबकि 27 भवनों, 18 पार्कों व खेल-मैदानों के नाम भी वीर सैनिकों को समर्पित किए गए हैं। ऐसे माहौल में यदि अग्रणी पूर्व सेनानायक सेना की सेवा को विवादों में घसीट लेते हैं तो सेना की गरिमा पर कुछ खरोंचें तो आएंगी।

सम्पादकीय...

मोदी और कार्नी : एक नए ग्लोबल ऑर्डर के रचयिता

इकोनॉमिक नेशनलिज्म के फिर से उभरने से दुनिया की राजनीति में पुराने रिश्ते हिल गए हैं और नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर में भरोसा डगमगा गया है। यह सबसे साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर के दौरान दिखा, जिसमें न सिर्फ दुश्मनों को, बल्कि साथियों को भी टारगेट किया गया। भारत, जो कभी अमेरिका की इंडो-पैसिफिक पॉलिसी में एक पसंदीदा पार्टनर था और कनाडा, जो एक अच्छा पड़ोसी और समय की कसौटी पर खरा उतरा दोस्त था, दोनों टैरिफ का शिकार हुए। मैसेज साफ था-स्वार्थ से चलने वाली दुनिया में, भरोसेमंद पार्टनर भी अब स्थिरता को हल्के में नहीं ले सकते। इसने मध्यम और उभरते देशों को ग्लोबल सिस्टम में अपनी जगह पर फिर से सोचने पर मजबूर किया। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और मार्क कार्नी के बताए गए विचार खास अहमियत रखते हैं। साथ मिलकर, अपने कामों और अपने आइडिया के जरिए, वे सहयोग और नियमों के सम्मान पर आधारित एक बैलेंस्ड ग्लोबल ऑर्डर की ओर इशारा करते हैं। दावोस में कार्नी ने समाज के उस हिस्से की आवाज बनकर बात की, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है-डिवेलप्ड और डिवेलपिंग दुनिया की 'मिडल पावर्स'। उनकी स्पीच ने बड़े पावर स्ट्रगल और आर्थिक संकटों में फंसे देशों की नाराजगी को साफ तौर पर दिखाया। इससे भी जरूरी बात यह है कि उन्होंने दुनिया को एक नई वोकैबुलरी दी, जिसने डिवेलप्ड और डिवेलपिंग देशों के बीच बढ़ते गैप को कम करने और एक साझा भविष्य की रक्षा करने की साझी जिम्मेदारी पर जोर दिया। कार्नी का संदेश साफ था-रूल्स-बेस्ड ऑर्डर पर दबाव है लेकिन यह न तो आउटडेटेड है और न ही रिप्लेसेबल। इसे रिफ्रेश करने की जरूरत है, छोड़ने की नहीं। इसी ग्लोबल इनस्टेबिलिटी के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रोच कम शोर वाली रही लेकिन कम असरदार नहीं। बयानबाजी की बजाय, भारत ने रणनीतिक आर्थिक राजनीति पर फोकस किया। ट्रेड वॉर के एक दौर के बाद, नई दिल्ली ने न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन जैसे पार्टनर्स के साथ उच्च गुणवत्तापूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को तेजी से आगे बढ़ाया है। ये एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत जरूरी स्थिरता देते हैं, खुलेपन के लिए भारत की कमिटमेंट दिखाते हैं और इसे ग्लोबल कैपिटल के लिए एक पसंदीदा मार्केट और गंतव्य बनाते हैं। सप्लाई चेन में रुकावटों और अस्थिर कैपिटल फ्लो के समय में, भारत स्थिरता का एक मजबूत पिलर बनकर उभरा है। इन दोनों अप्रोच का कॉम्बिनेशन-कार्नी की आइडियोलॉजिकल दिशा और मोदी का प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस-एक मजबूत कम्युनिटी के लिए स्टेज तैयार करता है। मार्च में कार्नी का भारत दौरा, जिसके दौरान एक बड़ी एनर्जी डील होने की संभावना है और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) पर बातचीत चल रही है, इस कॉम्बिनेशन को दिखाता है। एक मजबूत इंडिया-कनाडा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों को फायदा होगा-एनर्जी को-ऑपरेशन मजबूत होगा, सप्लाई चेन में ड्यूरेबिलिटी आएगी और इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ेगा। मोटे तौर पर, भारत और कनाडा दुनिया में स्थिरता के केंद्र बन सकते हैं।

थैंक यू, मोदी जी! आप उस दिन संसद में नहीं आए

भाई हम तो बिड़ला जी से सहमत हैं, पूरी तरह से। कौन से बिड़ला जी? बिड़ला हाउस वाले बिड़ला जी नहीं, नागपुरिया कुनबे वाले बिरला जी। लोकसभा की ऊंची कुर्सी वाले बिड़ला जी। बिड़ला जी ने दिल की गहराई से कहा--थैंक यू मोदी जी! थैंक यू मोदी जी, सलाह का मान रखने के लिए। थैंक यू मोदी जी, स्पीकर की सलाह मानकर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का जवाब देने के लिए लोकसभा में नहीं आने के लिए। मोदी जी अगर बिड़ला जी की सलाह सुनकर भी नहीं मानते और अपने भाषण के लिए टाइम पर लोकसभा में पहुंच जाते तो? अघट घट जाता, अघट। विपक्षी सांसदों ने जाने क्या ''अप्रत्याशित'' कर दिया होता। संसद की गरिमा, लोकसभा की परंपराओं और जनतंत्र की इज्जत तक, सब को विपक्षियों ने तार-तार कर दिया होता। पर मोदी जी की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी ने संसद की गरिमा, लोकसभा की परंपराओं और संसद की इज्जत का बाल भी बांका नहीं होने दिया। मोदी जी ने खुद ही न आकर, इन सारे खतरों को और वास्तव में विपक्षी षड्यंत्रों को ध्वस्त कर के रख दिया। न मोदी जी लोकसभा में आए और न विपक्षी वह अघट घटा पाए, जिसे घटाने का मोदी विरोधी विपक्ष का षड्यंत्र था। यह कोई न भूले कि बिड़ला साहब को विपक्षी षड्यंत्र की पक्की जानकारी थी। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा और इधर-उधर नहीं, खुद लोकसभा में अपने ऊंचे आसन पर बैठकर कहा कि उन्हें ''पुख्ता'' जानकारी मिली थी। और लोकसभा में जो दृश्य उन्होंने देखे थे, जिस तरह विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस तरह एक-दो नहीं पूरी तीन-तीन महिला सांसद, संसद के वेल में जाकर विरोध जता रही थीं, उससे उनकी जानकारियों की पुष्टि होती थी। ये महिला सांसद जहां थीं, वहां से प्रधानमंत्री का आसन जरा सी ही दूरी पर तो था। ये सांसद आसानी से प्रधानमंत्री को उनके आसन पर घेर सकती थीं। कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता था बल्कि कुछ भी अप्रत्याशित करने की विपक्ष की तैयारी थी। पर मोदी जी और बिड़ला जी ने मिलकर, इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को ही विफल कर दिया। मोदी जी आए ही नहीं। जब बाबा ही नहीं आए, तो घंटा कैसे बजता! पर बिड़ला जी के साथ-साथ मोदी जी का थैंक यू करना तो दूर रहा, उल्टे विपक्ष वाले इसका शोर मचा रहे हैं कि मोदी जी सवालों से डर कर भाग गए! बिड़ला जी ने संसद की परंपरा और डेमोक्रेसी वगैरह को बचाने के लिए भरी लोकसभा में मोदी जी का थैंक यू भी कर दिया, तब भी विपक्ष वाले भाग गए, भाग गए की रट लगाए हुए हैं। यह विपक्ष वालों की बेशर्मी को ही दिखाता है। लोकसभा वाला षड्यंत्र विफल हो गया, तब भी बेशर्मी से पीएम मोदी को बदनाम करने का षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी की छप्पन इंची छाती, कोरे प्रचार की चीज थी। नरवणे की फैसले की मांग से लेकर, एप्स्टीन फाइल और ट्रंप डील तक, जब भी नपने का सवाल आया, मिस्टर 56 इंच दुम दबाकर भाग गए। पर यह सब भी विपक्षी षड्यंत्र ही है--भारत के पीएम की छाती को छोटा कर के दिखाने का षड्यंत्र। विपक्षियों को यह हजम ही नहीं हो रहा है कि मोदी जी भारत को विश्व गुरु के आसन पर बैठाने से पहले ही, विश्व मल्ल के आसन पर कब्जा भी जमा चुके हैं। छप्पन इंची छाती का, बाकी ग्रहों की तो हम नहीं कहते, पर दुनिया भर के नेताओं में तो और कोई दावेदार है नहीं। और विरोधी जो बार-बार इसकी दलील दे रहे हैं कि तीनों महिला सांसद तो निहत्थी थीं, पिन से लेकर आलपिन तक उनके पास तो कुछ भी नहीं था, उनसे सैकड़ों भक्त सांसदों के बीच प्रधानमंत्री को क्या खतरा हो सकता था, उसका क्या? पर इस दलील में क्या वाकई कोई दम है? मोदी जी की गद्दी को सबसे बड़ी रक्षक, तेलुगु देशम के प्रवक्ता ने सत्तापक्ष की ओर से एकदम सही बताया है। महिला सांसदों के पास कोई हथियार न होने से क्या हुआ, उनके पास दांत तो थे। दांत भी थोड़े नहीं, एक-एक के करीब बत्तीस। सब मिलाकर सौ के करीब दांत। जरा सोचिए, अगर सौ दांतों से प्रधानमंत्री को काटा गया होता तो क्या होता? माना कि यह भी किसी न किसी तरह का विश्व रिकार्ड होता, पर राष्ट्र पर जो संकट आ जाता उसका क्या होता? बिड़ला जी को आइंदा सांसदों के दांतों के खतरे से पीएम की हिफाजत का भी कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। वैसे यही क्यों माना जाए कि प्रधानमंत्री पर संसद में महिला सांसदों के दांत हमले का ही खतरा था? बिड़ला जी ने कब कहा कि दांत हमले का ही खतरा था? उनकी पुख्ता जानकारी तो प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी ''अप्रत्याशित'' घट सकने की थी! सिर्फ दांत हमला ही क्यों, प्रधानमंत्री पर किताब हमला भी तो हो सकता था। क्या राहुल गांधी ने अपनी ओर से चाहे शेखी बघारते हुए ही सही, खुद ही सार्वजनिक रूप से इसका इशारा नहीं कर दिया था? क्या राहुल गांधी ने नरवणे की किताब दिखाते हुए कहा नहीं था कि प्रधानमंत्री सदन में आएंगे, तो वह उन्हें नरवणे की किताब देंगे। क्या यह प्रधानमंत्री के लिए अप्रत्याशित नहीं होता? रक्षामंत्री ने कहा कि नरवणे की किताब है ही नहीं, गृहमंत्री ने कहा कि किताब है ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि किताब है ही नहीं है, फिर भी किताब का वह भूत प्रधानमंत्री के हाथों में। सोचा है इसका नतीजा? साफ है कि राहुल का किताब ''देना'' सिर्फ शाब्दिक अर्थ में देना नहीं था। उसके खतरनाक अर्थ संकेत थे। थैंक यू मोदी जी इस संकट से देश को बचाने के लिए और थैंक यू बिड़ला जी, प्रधानमंत्री को इस संकट से देश को बचाने का रास्ता दिखाने के लिए। और यह सवाल करना तो विरोधियों की सरासर कठहुज्जती है कि अगर बिड़ला जी को सदन में मोदी जी के साथ कुछ अघट घटने की पुख्ता जानकारी थी, तो उन्होंने वह जानकारी, सुरक्षा के उपाय करने के लिए सरकार के अधिकारियों के साथ साझा क्यों नहीं की और प्रधानमंत्री को मौके से ही गायब हो जाने की सलाह क्यों दी? और जानकारी अगर पुख्ता थी, तो इस जानकारी पर अब षड्यंत्र के विफल हो जाने के बाद क्या कार्रवाई की जा रही है? लेकिन, ऐसे सवाल ही अनुचित हैं। बिड़ला जी सभी सांसदों के संरक्षक हैं और ऊपर से संस्कारी हैं; संसद की बात यानी उनके घर की बात और घर के मुखिया होने के नाते उन्हें घर की बात घर में ही निपटाना खूब आता है। पीएम के साथ अप्रत्याशित घट सकता था, नहीं घटा और षड्यंत्र करने वालों को चेतावनी भी मिल गयी, सांप भी मर गया और लाठी भी मर गयी। अमृतकाल में भला और क्या चाहिए? बस हमें बिड़ला जी से एक ही बात की शिकायत है। उन्होंने अपनी ओर से तो मोदी जी का थैंक यू किया, पर इतना तो काफी नहीं था। वह कम से कम 140 करोड़ भारतीयों की ओर से तो मोदी जी का थैंक यू कर ही सकते थे। मोदी जी ने कितने बड़े संकट से देश को बचा लिया। और विश्व को भी। आखिरकार, मोदी जी को किसी ने काट-वाट लिया होता, तो पूरी दुनिया उलट-पलट हो सकती थी। ट्रंप ने वैसे ही युद्ध रुकवाने के नाम पर, कई नये युद्ध छिड़वा दिए हैं। विश्व युद्ध भी छिड़ सकता था। इसलिए, 600 करोड़ पृथ्वी वासियों की ओर से थैंक यू भी हो जाता तो कोई गलत बात नहीं होती। खैर! बिड़ला जी के ही थैंक यू में सब का थैंक यू शामिल माना जाए।

डिजिटल युग में मिसिंग पर्सन्स की अफवाहें- भय, तथ्य, कानून और लोकतंत्र पर मंडराता संकट

वैश्विक स्तरपर इक्कीसवीं सदी का डिजिटल युग सूचनाओं की अभूतपूर्व शक्ति लेकर आया है। इंटरनेट सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स ने दुनियाँ को जोड़ दिया है,लेकिन इसी के साथअफवाहों और फेक न्यूज का संकट भी तेजी से बढ़ा है। आज भारत ही नहीं, बल्कि पूर्वविश्व इस चुनौती से जूझ रहा है कि किस प्रकार झूठी,भ्रामक और जानबूझकर फैलाई गई सूचनाएँ समाज, लोकतंत्र और मानव जीवन को गंभीर नुकसान पहुँचा रही हैं।यह स्थिति अब केवल सामाजिक या नैतिक चिंता का विषय नहीं रही,बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा चुनावी प्रक्रिया की शुचिता से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुकी है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि अफवाहों का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वे अक्सर सच का रूप धारण कर लेती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वायरल होने वाली सामग्री भावनाओं को भड़काने,डर फैलाने और पूर्वाग्रह को मजबूत करने का काम करती है।भारत जैसे विविधता-पूर्ण देश में, जहाँ भाषा, धर्म, जाति और राजनीतिक मतभेद पहले से मौजूद हैं,अफवाहें सामाजिक ताने-बाने को कमजोर कर देती हैं। वैश्विक स्तर पर भी,अफवाहों ने नस्लीय तनाव,युद्ध जैसी स्थितियों और कूटनीतिकसंबंधों को प्रभावित किया है।फेक न्यूज का सबसे पहला और सबसे गहरा प्रभाव सामाजिक सौहार्द पर पड़ता है। सांप्रदायिक अफवाहें, भ्रामक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और संदर्भ से काटे गए बयान अक्सर हिंसा, दंगों और सामाजिकतनाव को जन्म देते हैं।भारत में बीते वर्षों में कई घटनाएं सामने आई हैं जहां व्हाट्सएप्प संदेशों या सोशल मीडिया पोस्ट के कारण भीड़ हिंसा,लिंचिंग और सांप्रदायिक टकराव हुए। यह दर्शाता है कि अफवाहें केवल सूचना की समस्या नहीं हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का संकट बन चुकी हैंइसलिए अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि अफवाहों से निपटने के लिए केवल सामान्य कानून या प्लेटफॉर्म की स्वैच्छिक नीतियाँ पर्याप्त नहीं हैं। कुछ समय पूर्व मुंबई में मिसिंग पर्सन्स का मामला जोरशोर से उठ रहा था, मुंबई पुलिस द्वारा जारी चेतावनियों के बाद यह स्पष्ट हुआ कि मिसिंग पर्सन्स की संख्या पिछले वर्षों के औसत के अनुरूप ही थी,यानी अफवाहों पर कानूनी सख्ती की चेतावनी आई,मामला वहीं शांत हो गया।अब दिल्ली में मिसिंग पर्सन्स को लेकर फैली चर्चाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वास्तव में कोई असाधारण संकट है,या फिर यह डिजिटल अफवाहों द्वारा निर्मित सामाजिक भय है।दिल्ली में एक बड़ी न्यूज एजेंसी द्वारा यह दावा किया गया कि 2026 के पहले 15 दिनों में दिल्ली में 800 से अधिक लोग लापता हो गए। यह संख्या सुनने में भयावह लगती है,लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि कितने मामले पारिवारिक विवाद, स्वेच्छा से, एग्जाम का डर, युवकों की नासमझी, लव अफेयर्स से घर छोड़ने या फिर गलत रिपोर्टिंग से जुड़े हैं।सोशल मीडिया पर वीडियो, ऑडियो क्लिप और भावनात्मक पोस्ट वायरल हो रहे हैं। एक बड़े नेता द्वारा एक्स (पूर्व ट्विटर) पर चिंता व्यक्त किए जाने के बाद यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया।हालाँकि, जब आँकड़ों का विश्लेषण किया गया तो सामने आया कि दिल्ली में मिसिंग पर्सन्स की रिकवरी दर लगभग 77 प्रतिशत है। अर्थात, लापता घोषित किए गए लोगों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षित रूप से वापस मिल जाता है।यह दर कई अंतरराष्ट्रीय महानगरों की तुलना में बेहतर मानी जाती है।मीडिया के हवाले से सुनने को मिला है कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि हाल के अलग-अलग महीनों में मिसिंग पर्सन्स की जो संख्या बताई जा रही है वैसी ही संख्या पिछले वर्षों की औसत अवधि से भिन्न नहीं है तथा दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी का बयान मैंने सुना उन्होंने कहा कि अफवाओं पर ध्यान ना दें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर अफवाहों का प्रभाव अत्यंत चिंताजनक है। चुनावों के दौरान फेक न्यूज मतदाताओं की सोच को प्रभावित करती है, उम्मीदवारों की छवि बिगाड़ती है और चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। भारत में हाल के वर्षों में चुनावी समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई भ्रामक जानकारियां इसका उदाहरण हैं।कई देशों में चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप और संगठित फेक न्यूज अभियानों की पुष्टि हुई है।

यदि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है, तो अफवाहों को केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। साथियो बात अगर हम जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में अफवाहों का प्रभाव और भी घातक सिद्ध हुआ है इसको समझने की करें तो कोविड-19 महामारी के दौरान दुनियाँ ने देखा कि कैसे झूठी सूचनाओं ने वैक्सीन को लेकर डर पैदा किया, इलाज के नाम पर खतरनाक घरेलू नुस्खों को बढ़ावा दिया और स्वास्थ्य प्रणालियों पर अविश्वास फैलाया।भारत सहित कई देशों में अफवाहों के कारण लोगों ने समय पर इलाज नहीं कराया, जिससे जानमाल की क्षति हुई। यह स्पष्ट है कि जब अफवाहें जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाएँ, तब उन्हें रोकना केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कानूनी आवश्यकता बन जाती है।भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्मों की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है।व्हाट्सएप्प फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अफवाहों के सबसे बड़े वाहक बन चुके हैं।एंड-टू-एंडएन्क्रिप्शन अनियंत्रित फॉरवर्डिंग और एल्गोरिदम आधारित कंटेंट प्रमोशन ने झूठी खबरों को पलक झपकते ही लाखों लोगों तक पहुँचा दिया है। वर्तमान भारतीय कानून, जैसे आईटी एक्ट या आईपीसी की कुछ धाराएँ, इस समस्या से निपटने के लिए अपर्याप्त साबित हो रही हैं। ये कानून अफवाहों की गति, पैमाने और जटिलता को ध्यान में रखकर नहीं बिलकुल बनाए गए थे। साथियों बात अगर हम पेड प्रमोशन और डर कॉमर्शियलाइजेशन(?) इस एंगल से समस्या को समझने की करें तोअफवाहों के पीछे केवल अज्ञानता ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक हित भी संभवतः काम कर रहे हैं।आज कई इन्फ्लुएंसर्स, पेज और चैनल जानबूझकर डरावनी सामग्री फैलाते हैं क्योंकिइससे व्यूज बढ़ते हैं,एंगेजमेंट मिलता है पेड प्रमोशन और ब्रांड डील्स आती हैं,यह एक प्रकार की डर आधारित मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है,जिसमें समाज की असुरक्षा को उत्पाद की तरह बेचा जाता है।कानून की सीमाएँ- क्या मौजूदा प्रावधान पर्याप्त है?

भारत में आईटी एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और अन्य कानूनों में अफवाहों से निपटने के कुछ प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन वेविशिष्ट नहीं हैं। साथियों बात अगर हम इसी संदर्भ में,एक विशिष्ट और सख्त कानून लाने की आवश्यकता की करें तो, फेक न्यूज एक्ट की आवश्यकता महसूस की जा रही है,जो अफवाहों को स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में रखे। ऐसा कानून न केवल जानबूझकर झूठी सूचना फैलाने वालों के लिए दंडात्मक प्रावधान तय करे, बल्कि यह भी परिभाषित करे कि अफवाह, फेक न्यूज और भ्रामक सूचना क्या है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समान ढाँचे की दिशा में प्रयास आवश्यक है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्मों की वैश्विक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए देशों के बीच सहयोग संभव हो सके।हालाँकि, केवल कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं होगा। यदि नागरिक स्वयं सही और गलत जानकारी की पहचान करने में सक्षम नहीं होंगे, तो अफवाहें किसी न किसी रूप में फैलती रहेंगी। इसलिए व्यापक स्तर पर डिजिटल साक्षरता और मीडिया साक्षरता अभियानों की आवश्यकता है। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक स्तर पर लोगों को यह सिखाना जरूरी है कि किसी खबर की सत्यता कैसे जाँची जाए,स्रोत की विश्वसनीयता कैसे परखी जाए और भावनात्मक अपील से सावधान कैसे रहा जाए।जागरूक नागरिक ही अफवाहों के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल बन सकते हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियों की जिम्मेदारी भी इस पूरे तंत्र में केंद्रीय है। अब यह मान लेना गलत होगा कि ये कंपनियाँ केवल मध्यस्थ हैं। इनके एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि कौन-सा कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुँचेगा। इसलिए इन्हें कानूनी रूप से बाध्य किया जाना चाहिए कि वे कंटेंट मॉडरेशन को मजबूत करें, फॉरवर्ड की संख्या पर सख्त सीमाएँ लगाएँ और संदिग्ध सामग्री पर त्वरित कार्रवाई करें। भारत में व्हाट्सएप्प द्वारा फॉरवर्ड लिमिट जैसी पहलें हुई हैं, लेकिन इन्हें स्वैच्छिक प्रयासों से आगे बढ़कर कानूनी दायित्व बनाना आवश्यक है। साथियों बात कर हम फेक न्यूज मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तरपर समझने की करें, इस समस्या का समाधान सामूहिक प्रयास से ही संभव है। संयुक्त राष्ट्र, जी-20 और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर फेक न्यूज और अफवाहों के खिलाफ साझा मानक तय किए जाने चाहिए। साइबर स्पेस की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, इसलिए एक देश में फैली अफवाह दूसरे देश को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में वैश्विक सहयोग,सूचना साझाकरण और संयुक्त नियामक ढाँचा समय की मांग है। अतःअगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अफवाहें आज के समय में एक मौन लेकिन शक्तिशाली हथियार बन चुकी हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने बदरा ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, साउथ पैचराबत एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08862)

कार्यदायी संस्थाएं तय सीमा में हैण्डओवर करें परियोजनाएं: डीएम

मुरादाबाद।

50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न

जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद मुरादाबाद में 50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि जनपद में जो भी निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं उन पर आने जाने का रास्ता हो, इसको सुनिश्चित किया जाये तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर पूर्णतया ध्यान रखा जाये। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्धारित समयावधि में अपनी निर्माण परियोजनाओं को पूर्ण कर हैण्डओवर कराना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्था यूपीसीएनडीएस द्वारा राजकीय प्रक्षेत्र गौण्डा के सुदृढ़ीकरण में भौतिक प्रगति धीमी होने पर असंतोष व्यक्त करते हुए समय से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. द्वारा जनपद मुरादाबाद की ग्राम पंचायत रतनपुर कलां में स्टेडियम ओपन जिम निर्माण तथा बिलारी में गन्ना किसान संस्थान की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कार्यदायी संस्था सीएनडीएस द्वारा मुढापाण्डे में आईटीआई का निर्माण एवं फर्नीचर उपकरण तथा बिलारी में प्रशासनिक भवन निर्माण, कन्वेंशन सेंटर एवं मैरिज हॉल निर्माण तथा नगर पंचायत महमूदपुर माफी में पंचायत घर में पुस्तकालय शूट सेंटर को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश रा'य सेतु निगम द्वारा पंडित नगला बाईपास पर रेलवे क्रासिंग ऊपरीगामी सेतु के निर्माण की भौतिक प्रगति 73.88 प्रतिशत होने पर जिलाधिकारी ने समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एकेडमिक ब्लाक एवं बालिका छत्रावास भवन निर्माण की भौतिक प्रगति लक्ष्य के सापेक्ष न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उ.प्र. जल निगम ग्रामीण द्वारा रुस्तमनगर सहसपुर में सोलर पैनल एवं मिट्टी भराव का कार्य कैम्पस में शेष रहने पर जिलाधिकारी ने जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने उ.प्र. जल निगम नगरीय, यूपी सिडको, सीएनडीएस, उ.प्र. पर्यटन विकास निगम, उ.प्र. राज्य सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग,प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड प्रथम लोक निर्माण विभाग, नलकूप विभाग, उ.प्र. वक्फ विकास निगम लिमिटेड, पैकफेड आदि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विकास अधिकारी जीबी पाठक, परियोजना अधिकारी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रबन्धक/ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

डीआईजी ने किया एसएसपी कार्यालय का मुआयना

मुरादाबाद। डीआईजी मुनिराज ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआईजी, एसएसपी कार्यालय में स्थित विभिन्न शाखाओं पर पहुंचे और अभिलेख वगैरह चैक करने के साथ ही सम्बन्धित पटल सहायकों से आवश्यक पूछताछ भी की। उन्होंने निर्देश दिये कि कार्यों में लापरवाही कतई न बरती जाये। दस्तावेजों को रख रखाव सही तरह से रहे। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने एसएसपी कार्यालय पहुंचे फरियादियों की शिकायतों को भी सुना और उनके गुणवत्ता परक निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित न्याय मिलना चाहिए, यही सरकार की मंशा है। इस दौरान एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी सिटी रणविजय सिंह, एसपी ग्रामीण कुंवर आकाश सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में मनाया गया महाशिवरात्रि महोत्सव

मुरादाबाद। मिलन बिहार के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका भी के निर्दोष दीदी बीके भावना दीदी के द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव बहुत ही उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव में बड़ी संख्या में भाई बहनों ने हिस्सा लिया कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेविका रितु नारंग, आनंद चाइल्ड हेल्थ केयर के फाउंडर डॉक्टर आनंद चौधरी, डीजीओ गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता चौधरी मौजूद रहे और साथ ही मुरादाबाद के ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्रों की इंचार्ज राजयोगिनी आशा दीदी, शील दीदी, सुमित्रा दीदी भी पहुंचे। कार्यक्रम में शिवरात्रि के महत्व को और उसके आध्यात्मिक रहस्य को बहुत ही सुंदर तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बताया गया। शिवरात्रि में ध्वजारोहण और दीप प्र'वलन भी किया गया और बहुत सुंदर विधि बताई,कैसे राजयोग के द्वारा हम शिव से अपना सम्बन्ध जोड़े,जो कि हम सभी आत्माओं के पिता है। उनसे अपना सम्बन्ध जोड़कर खुद को दुःखों से मुक्त करें।

कलश यात्रा का पुष्पवर्षा से हुआ स्वागत

मुरादाबाद। इंपीरियल तिराहा स्थित श्री मनोकामना हनुमान मंदिर में राम दरबार का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। शुभारंभ कलश यात्रा से किया गया। कलश यात्रा गुलजारी मल धर्मशाला से आरंभ की गई। महिलाएं सिर पर कलश लिए चलती रहीं। रास्ते भर भक्ति संगीत गूंजता रहा। श्रद्धालु भजन कीर्तन करते रहे। रास्ते भर जय श्री राम का जयघोष होता रहा। व्यापारियों सहित अन्य लोगों ने रास्ते में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मंदिर पहुंचकर कलश स्थापना की गई। मंदिर में भजन कीर्तन किया गया। बाद में श्री राम को भोग लगाकर भंडारा आरंभ किया गया। मुख्य अतिथि अल्पना रितेश गुप्ता रहीं। व्यवस्था में डा. प्रमोद कुमार गुप्ता, वेद वाला गुप्ता, सलोनी, बकुल, मनी, विनय, दिव्या, अपन, निपेंद्र कुमार, वंश, राहुल, ओमप्रकाश सहित शिव मंदिर सागर सराय के महिला मंडल का भी सहयोग रहा।

महिला अधिवक्ताओं ने कहा-बिना भेदभाव प्रत्येक महिला की सुरक्षा का रखा जाए ध्यान

फतेहपुर।

आज महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है। उनकी सुरक्षा और मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उससे हर आम व खास महिला के अन्दर भय समाया हुआ है। महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रही उत्पीड़नात्मक घटनाओं को लेकर महिला अधिवक्ताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिना भेदभाव प्रत्येक महिला की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए और हर खास-ओ-आम महिला को सम्मान मिलना चाहिए। किसी एक महिला का अपमान मतलब आधी आबादी का अपमान है। माहीनम हारून एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद ने कहा कि महिला कोई भी हो, सबका अपना सम्मान और स्वाभिमान होता है। अधिवक्ता आरती पाण्डेय के साथ टोल पर जिस तरह से हाथापाई की गई, वह बहुत ही निंदनीय है। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हर क्षेत्र के लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। निशा गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ सभी को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। महिलाओं के सम्मान से ही समाज का सम्मान है। कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ती अत्याचार की घटनाओं से महिलाओं में भय समाया हुआ है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। रूही एडवोकेट ने कहा कि सोनभद्र में रावर्टगंज कोतवाली क्षेत्र के लोढ़ी टोल प्लाजा पर अधिवक्ता आरती पाण्डेय के साथ घटित हुई घटना बहुत ही निन्दनीय है। कर्मचारियों की गुण्डई का आलम यह है कि वह एक महिला से मारपीट पर उतर जाते हैं। ऐसे अपराधियों को ऐसी सजा मिले कि घटना की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने यह भी कहा कि परिचय देने पर प्राथमिकता पर बात सुनी जानी चाहिए। पुष्पा मौर्या एडवोकेट ने कहा कि हर महिला के मान सम्मान का ध्यान रखा जाना चाहिए। रही अधिवक्ता की बात, तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।

किसी एक महिला का अपमान मतलब आधी आबादी का अपमान

आखिर यह टोल वाले महिला पर हाथ उठाने वाले होते कौन है ? किसी एक महिला का अपमान मतलब आधी आबादी का अपमान है। कहा कि उनकी मांग है कि अधिवक्ताओं के लिए टोल फ्री किया जाए। रुखसार एडवोकेट ने कहा कि महिलाओं के साथ अत्याचार व न्याय में जो दोहरी नीति अपनाई जाती है, वह बहुत ही निन्दनीय है। इसी कारण लोगों का मन इतना बढ़ गया है कि महिला अधिवक्ता पर भी हाथ उठा रहे हैं। कहा कि अधिवक्ता आरती पाण्डेय प्रकारण की जितनी निन्दा की जाए वह कम है। अलफिशा एडवोकेट ने कहा जहां भी पब्लिक से सीधे जुड़ने का मामला है, वहां पर बहुत ही शालीन और सभ्य लोगों को बैठाना चाहिए। लेकिन टोल पर बैठने वालों कर्मचारियों की हरकत से ऐसा लगता है कि वहां पर गुण्डों को बैठाया जाता है। जो ठीक नहीं है।

मिश्रपुर में दो दिवसीय ओपेन वॉलीबाल प्रतियोगिता संपन्न

मेजा प्रयागराज।

अंसार क्लब मंडौर ने जीती वॉलीबाल प्रतियोगिता की ट्रॉफी. आईटीआई कॉलेज नैनी की टीम बनी उपविजेता

स्थानीय मिश्रपुर गाँव के क्रीड़ा स्थल पर वॉलीबाल क्लब मिश्रपुर द्वारा डिस्ट्रिक्ट वॉलीबाल एसोसिएशन (डीवीए), प्रयागराज के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय ओपेन वॉलीबाल प्रतियोगिता सोमवार को संपन्न हुई। प्रतियोगिता में जनपद की कुल 14 टीमों ने प्रतिभाग कर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया था। पहले दिन प्रतियोगिता का शुभारंभ भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रभाशंकर उर्फ रिंकू ओझा ने फीता काटकर किया था। प्रतियोगिता का फाइनल मैच अंसार क्लब मडौर, फूलपुर और आईटीआई कॉलेज नैनी के बीच खेला गया। जिसमें अंसार क्लब मंडौर,फूलपुर की टीम ने आईटीआई कॉलेज नैनी की टीम को 25 - 20 व 25 - 18 अंकों से हराकर दो दिवसीय ओपेन वॉलीबाल प्रतियोगिता की चैंपियन ट्रॉफी जीत कर अपने नाम कर ली। प्रतियोगिता के दौरान अल्ताफ अली, मुकेश शुक्ला, असफाक अहमद, राकेश कुमार व आकाश कुमार ने निर्णायक का कार्य किया। प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नायब तहसीलदार मेजा नंदलाल ने फाइनल मैच शुरू होने से पूर्व दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और विजेता टीम अंसार क्लब मंडौर,फूलपुर के कप्तान को चैंपियन ट्रॉफी व दस हजार रुपये नगद तथा उपविजेता टीम आईटीआई नैनी के कप्तान को ट्रॉफी व सात हजार रुपये नगद प्रदान किया। आयोजन समिति के संरक्षक राम सिंह पूर्व प्रधान मिश्रपुर ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय का बैच लगाकर व माल्यार्पण कर स्वागत किया। डिस्ट्रिक्ट वॉलीबाल एसोसिएशन, प्रयागराज के नवनिर्वाचित महासचिव आर.पी.शुक्ला व कोषाध्यक्ष के.बी.एल.श्रीवास्तव ने सेमीफाइनल मैच शुरू होने से पूर्व दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं प्रतियोगिता के खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में आईटीआई कॉलेज नैनी ने स्पोर्टिंग क्लब ऊंज की टीम को 29 - 27 व 25 - 18 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश की थी। दूसरे सेमीफाइनल मैच में अंसार क्लब मंडौर,फूलपुर ने मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रयागराज की टीम को 23 - 25, 25 - 12 व 25 - 22 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। कार्यक्रम का सफल संचालन सुरेश चौबे, मुकेश सिंह व मुनीम शंकर ने किया। वॉलीबाल क्लब मिश्रपुर के अध्यक्ष टी.एन.सिंह ने प्रतियोगिता में पधारे अन्य अतिथियों का बैच व माल्यार्पण कर स्वागत किया। आयोजन समिति की ओर से प्रभाकर चौबे ने प्रतियोगिता में पधारे सभी अतिथियों व खिलाड़ियों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। उक्त अवसर पर रामनगर प्रधान प्रतिनिधि नीरज यादव, सुबालाल सोनकर, सोनू यादव, पूर्व वॉलीबाल खिलाड़ी अंशु सिंह, फतेह बहादुर यादव,राकेश सिंह ,धनंजय प्रजापति पत्रकार,राजन मिश्रा, चंद्रमोहन राव, बी.के.केसरी, अजय कुमार, राजन यादव, ठाकुर यादव व अजय सिंह आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहें।

स्वछता के दावे हवा, गोट में गंदगी का अंबार, गांव की नालियों में भरी कीचड़

मुरादाबाद। ग्राम पंचायत गोट में सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर, बंद नालियां और जलभराव स्वछता की हकीकत बयां कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद रास्तों पर महीनों से कूड़े के ढेर लगे हैं। ग्रामीणों को मजबूरी में खुद ही नालियों में भरी कीचड़ हाथ से निकालनी पड़ रही है, जिसे उन्होंने मौके पर दिखाकर अपनी पीड़ा जाहिर की। जिससे लोगों में रोष है। रविवार को मुरादाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत गोट की गलियों में लंबे समय से जमा कूड़ा साफ दिखाई दिया। गांव निवासी राजवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार शर्मा से मिलकर गंदगी की लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। ग्रामीणों के अनुसार मुख्य सड़क पर स्थित नालियां पूरी तरह बंद हैं, जिससे जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान असलम हुसैन इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं सफाई कर्मचारी सविता गांव में करीब 15 दिन में एक बार आती हैं और प्रधान के निर्देशानुसार सीमित सफाई कर चली जाती हैं।गांव के प्राथमिक विद्यालय के गेट से लगा नाला कूड़े से पूरी तरह बंद पड़ा है, जिससे उठ रही दुर्गंध वातावरण को दूषित कर रही है। सड़कों पर भरे पानी के बीच से गुजर कर ग्रामीणों को अपने घरों तक आना-जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले छह महीनों से इस समस्या को झेल रहे हैं, लेकिन शिकायत करने पर भी प्रधान और सचिव द्वारा केवल टालमटोल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि गांव में नियमित सफाई कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। घर के सामने काफी लंबे समय से नालियां बंद पड़ी हैं। जिसकी वजह से घर के आगे हर वक्त गंदी पानी भर रहा है। घर में आने पर पहले पैर धोने पड़ते हैं, नहीं तो गंदे पानी के बीच से गंदगी घर में आती है।- सर्वेश कुमारी, गांव निवासी। गांव निवासी अर्जुन सिंह ने बताया कि प्राइवेट बैंक में मैनेजर हूं लेकिन हर दूसरे दिन मुझे घर के आगे बनी नाली में भरी कीचड़ को साफ करना पड़ता है। कई बार प्रधान से कहा, लेकिन नालियों में भरी कीचड़ नहीं निकलवाई गई। उप निदेशक पंचायत राज अभय कुमार के मुताबिक अभी फिलहाल डीपीआरओ छुट्टी पर हैं।

पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक सोशल मीडिया पर लीक, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

नई दिल्ली।

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की आगामी किताब फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कथित रूप से सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, इस पुस्तक को अभी संबंधित प्राधिकरणों से प्रकाशन की आवश्यक अनुमति नहीं मिली है।

प्री-प्रिंट कॉपी इंटरनेट पर किसने की अपलोड?

दिल्ली पुलिस ने बताया कि विभिन्न ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज फोरम पर ऐसी जानकारी सामने आई थी कि किताब की प्री-प्रिंट कॉपी इंटरनेट पर साझा की जा रही है। इन दावों के संज्ञान में आने के बाद पुलिस

ने मामले की जांच शुरू की।

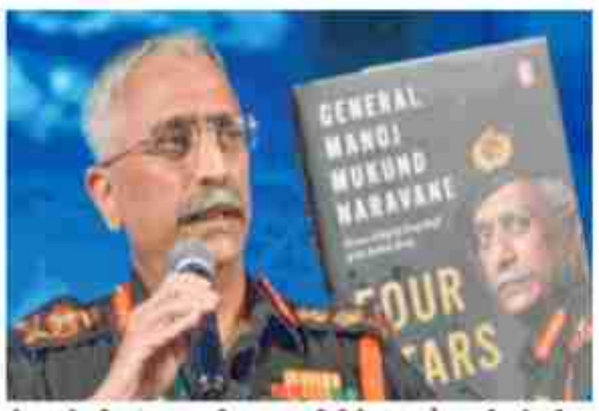

पुस्तक का फाइनल कवर भी प्रदर्शित

शुरुआती जांच में पाया गया कि फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी शीर्षक से टाइपसेट की गई एक पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। यह कॉपी कथित रूप से पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की गई प्रतीत होती है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर पुस्तक का फाइनल कवर भी इस तरह प्रदर्शित किया गया है, मानो वह बिक्री के लिए उपलब्ध हो।

गोपनीयता का उल्लंघन

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, यह मामला एक ऐसी पुस्तक के संभावित लीक या गोपनीयता उल्लंघन से जुड़ा है, जिसे अभी आधिकारिक मंजूरी मिलना बाकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल में केस दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।

खोजे जा रहे इन सवालों के जवाब

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि पुस्तक की प्री-प्रिंट कॉपी ऑनलाइन कैसे पहुंची, इसमें किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका हो सकती है, और क्या इसमें कॉपीराइट या अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किताब पर विवाद

*दिल्ली पुलिस ने सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के लीक होने पर एफआईआर दर्ज की है

*पुस्तक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की प्री-प्रिंट प्रति बिना अनुमति ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर सर्कुलेट हो रही थी

*पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा तैयार पीडीएफ कॉपी कुछ वेबसाइटों पर उपलब्ध मिली है

ओम बिरला पर कांग्रेस का चिट्ठी बम, कहा- मोदी को बचाने के लिए हमें बदनाम किया

नई दिल्ली । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सांसदों ने सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी ने उन्हें उनके खिलाफ झूठे, निराधार और मानहानिकारक दावे करने के लिए मजबूर किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया था ताकि कोई अप्रिय घटना न हो, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ कांग्रेस सांसद सदन में प्रधानमंत्री की सीट पर आकर अभूतपूर्व घटना को अंजाम दे सकते हैं। सांसदों ने कहा कि सदन में उनका विरोध शांतिपूर्ण और संसदीय मानदंडों के अनुरूप था, लेकिन उन्हें अभूतपूर्व रूप से निशाना बनाया गया। पत्र में सांसदों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लगातार चार दिनों तक बोलने का अवसर नहीं दिया गया, जबकि एक भाजपा सांसद को पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में अश्लील और अभद्र टिप्पणी करने की अनुमति दी गई। सांसदों ने आगे दावा किया कि जब वे भाजपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए स्पीकर से मिले, तो उन्होंने गंभीर गलती स्वीकार की, लेकिन बाद में संकेत दिया कि वे सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वे अब ऐसे मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते हैं। अगले दिन, सांसदों ने दावा किया कि स्पीकर ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति को उचित ठहराने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में आकर एक बयान जारी कर उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। सांसदों ने जोर देकर कहा कि उनका विरोध निरंतर शांतिपूर्ण, दृढ़ और पूरी तरह से लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुरूप था। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनमें से कई साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और पहली पीढ़ी के राजनेता हैं जिन्होंने प्रतिरोध और भेदभाव के बावजूद दशकों की सार्वजनिक सेवा के माध्यम से अपना करियर बनाया है। सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लगातार जवाबदेह ठहराने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री का सदन से अनुपस्थित रहना उनकी ओर से किसी खतरे का जवाब नहीं बल्कि डर का एक कार्य था।

पाकिस्तान के एजेंट वाले आरोप पर भड़के गोगोई, बोले- सीएम की कुर्सी के लायक नहीं हिमंता बिस्वा

असम। असम कांग्रेस अध्यक्ष और जोरहाट सांसद गौरव गोगोई ने सोमवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के पाकिस्तान कनेक्शन के आरोपों पर पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बच्चों की जानकारी मीडिया में लीक की है। मुख्यमंत्री सरमा ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट जारी करते हुए आरोप लगाया कि गौरव गोगोई, उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई और एक पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के बीच गहरे संबंध हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि एसआईटी कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि कल ढाई घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं

कर सके जिससे यह साबित हो सके कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूं। वे गोलमोल बातें करते रहे। उनके पास पिछले छह महीनों से एसआईटी की रिपोर्ट है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि वे 10 सितंबर को एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो हमारा सिर्फ एक ही सवाल है- मुख्यमंत्री पिछले छह महीनों से इस रिपोर्ट पर चुप क्यों रहे? इसका कारण यह है कि उनके द्वारा गठित एसआईटी कोई सबूत पेश करने में असफल रही। कांग्रेस सांसद ने फिर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सरमा के परिवार ने असम भर में 12,000 बीघा (लगभग 4,000 एकड़) जमीन अवैध रूप से अपने पास रखी हुई है। उन्होंने मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) के साथ सहयोग करने की सहमति जताते हुए एसआईटी की रिपोर्ट जारी करने की मांग की। गोगोई ने कहा कि कल की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता है... अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता, तो वह (असम के मुख्यमंत्री) पिछले छह महीनों से निष्क्रिय क्यों बैठे थे? कांग्रेस पार्टी द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद कि मुख्यमंत्री के परिवार के पास 12,000 बीघा जमीन है, मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

गृहमंत्री शाह बोले: बस्तर की पहचान बारूद नहीं, संस्कृति है, बस्तर पंडुम में कहा- जल्द होगा नक्सलवाद का सफाया

रायपुर । केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि बस्तर की पहचान बारूद और हिंसा नहीं, बल्कि इसकी समृद्ध संस्कृति, कला और विरासत है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले तक बस्तर नक्सल भय, दूरस्थ धमाकों और गोलियों की आवाज से दहला रहता था, लेकिन आज 55 हजार से अधिक आदिवासी खान-पान, गीत, नृत्य, नाटक, वेशभूषा, परंपरा और वन औषधि सहित 12 विधाओं में अपनी संस्कृति को जीवंत कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर पंडुम इस बात

का प्रमाण है कि बस्तर अब नक्सल डर से मुक्त होकर विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 7 जिलों, 1885 ग्राम पंचायतों और 32 जनपदों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी सरकार आदिवासी समाज की संस्कृति, कला और पहचान को वैश्विक मंच पर सम्मान दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस और 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित करना इसी सोच का परिणाम है। नक्सलवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए गृह मंत्री ने कहा कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, सरकार उनका सम्मानपूर्वक पुनर्वास करेगी, लेकिन जो हथियार उठाएंगे, उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का मूल उद्देश्य आदिवासी किसानों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा है।

उन्होंने बताया कि आने वाले 5 वर्षों में बस्तर को आदिवासी क्षेत्रों में सबसे विकसित क्षेत्र बनाया जाएगा। 118 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र, नई पर्यटन गतिविधियां, रेल परियोजनाएं, सिंचाई योजनाएं और रोजगार के अवसर बस्तर के भविष्य को नई दिशा देंगे। अमित शाह ने कहा कि बस्तर अब एक राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में उभर रहा है और तय समय सीमा में यह क्षेत्र पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा।

मोहम्मद दीपक को जान से मारने की धमकी, इनाम भी घोषित, कोटद्वार में बाबा नाम पर उठा था विवाद

कोटद्वार । कोटद्वार में दुकान का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद के बीच चर्चाओं में आए मोहम्मद दीपक को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली है। साथ ही दो लाख रुपये का इनाम रखा गया है। दीपक कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रथम दृष्टया आरोपी की पहचान राजा उत्कर्ष, निवासी मोतिहारी, बिहार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमीअत उलेमा-ए-हिंद उत्तराखंड ने डीजीपी को पत्र लिखकर कोटद्वार प्रकरण में दीपक कुमार को सुरक्षा देने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि दीपक कुमार ने 26 जनवरी को एक मुस्लिम दुकानदार पर हुए हमले के दौरान बीच-बचाव कर व्यापारी की जान बचाई। अब उन्हें जान का खतरा बना हुआ है।

लोकसभा में रार: राहुल का दावा- अध्यक्ष ने बोलने का दिया था आश्वासन, अब वह वादे से मुकर रहे; रिजिजू ने किया खंडन

नई दिल्ली।

लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को हंगामे के बीच दो बार स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्षी सांसदों द्वारा भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार सौदे पर चर्चा की मांग जारी रखने के चलते सदन को फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से यह आश्वासन दिया गया था कि बजट पर चर्चा शुरू होने से पहले उन्हें कुछ बिंदु रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन अब लोकसभा अध्यक्ष अपने वादे से पीछे हट रहे हैं।

लोकसभा अध्यक्ष अपने वादे से पीछे हट रहे हैं

राहुल गांधी ने कार्यवाही की अध्यक्षता कर रही सांसद संध्या राय से कहा, अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप

■ **राहुल बोले- स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे- रिजिजू बोले- कोई कमिटमेंट नहीं, लोकसभा स्थगित; विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है**

से हमसे वादा किया था कि मुझे बजट पर चर्चा से पहले यहां बोलने की अनुमति दी जाएगी। अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे उन मुद्दों पर बोलने की अनुमति दी जाएगी या नहीं?

राहुल के दावे पर क्या बोले रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने

कहा राहुल गांधी ने कहा कि वेणुगोपाल जी स्पीकर के चैंबर में थे। मैं भी शामिल हुआ और हमने चर्चा की।

मैं यह कन्फर्म करना चाहता हूं कि स्पीकर ने यह पहल किया कि अगर सब सहमत हों, तो सदन चलना चाहिए और वेणुगोपाल जी ने भी कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे विपक्ष के नेता कुछ कहें। लेकिन उससे पहले, हमने तय किया कि आप किस टॉपिक पर बोलेंगे?... स्पीकर ने यह कहा कि राहुल गांधी ने अभी जो कहा वह 100 परसेंट सही नहीं है। स्पीकर ने कोई वादा नहीं किया है। स्पीकर ने कहा कि अगर कोई समझौता होता है, तो हम आपको बोलने देंगे और हम दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी बोलने देंगे। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम सिर्फ कांग्रेस को ही बोलने देंगे...। विपक्ष के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया है। उनका आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही में पक्षपाती रवैया अपनाया है और विपक्ष की आवाज़ को दबाया है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर प्रतिक्रिया दी है और इसे संसद की परंपरा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, स्पीकर साहब का खुद निरादर किया गया है। स्पीकर साहब पर दबाव है कि उनको खुद बयान देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। सवाल ही नहीं उठता कि पीएम पर कोई हमला करे। सरकार द्वारा उन पर दबाव डाला गया है इसलिए उन्होंने ये कहा है क्योंकि उस दिन पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई सदन में आने की। इसलिए स्पीकर सफाई दे रहे हैं, ये गलत बात है।

थरूर ने सरकार पर लगाए आरोप

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हालात बहुत स्पष्ट हैं, मुझे नहीं पता कि सरकार या स्पीकर क्यों नहीं चाहते कि सदन में बजट पर बहस हो। बहुत साफ़ तौर पर, कई वर्षों से सदन की एक पुरानी परंपरा रही है। दो लोगों को हमेशा बोलने का मौका दिया जाता है, एक नेता प्रतिपक्ष और दूसरे संसदीय कार्य मंत्री... हमारे पास दो पीठासीन अधिकारी थे जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देने से मना कर दिया, जबकि संसदीय कार्य मंत्री जब भी हाथ उठाते हैं, उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है,

यह सही नहीं है। सदन हम सबका है... उन्हें(राहुल गांधी) अपनी बात रखने की इजाज़त मिलनी चाहिए... मुझे समझ नहीं आता कि सरकार और स्पीकर क्या चाहते हैं... संसद में दोनों पक्षों को बोलने का अधिकार होता है लेकिन एक पक्ष को बोलने से पूरी तरह से रोक देना बिल्कुल गलत है।

अधिकारियों के नाम भेजने में देरी क्यों? एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछे कई सवाल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस याचिका पर चुनाव आयोग का जवाब सुन रहा है, जिसमें राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में 1.36 करोड़ से ज्यादा वोटर्स की एक लॉजिकल गड़बड़ी वाली लिस्ट का मुद्दा उठाया है। उन्होंने दावा किया कि इन वोटर्स के नाम सरनेम में गलत स्पेलिंग या शादी के बाद बेटियों के पते बदलने जैसी सिस्टमैटिक गलतियों के आधार पर हटाए जाने का खतरा है। ममता ने राज्य में चुनाव योग द्वारा नियुक्त किए गये 8,300 माइक्रो-ऑब्जर्वर की तैनाती का मुद्दा भी उठाया, जिन्हें उन्होंने केंद्र सरकार के अधिकारी होने का दावा किया है। ममता ने बिना किसी अधिकार के गैर-संवैधानिक तरीके से वोटर्स के नाम हटाने की भी बात कही है।

कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट का तत्काल जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली । सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बलात्कार के दोषी और पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय को उनकी अपील पर सुनवाई करने और तीन महीने के भीतर जमानत पर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि न्यायालय सेंगर की 10 साल की सजा पर रोक नहीं लगा रहा है, लेकिन उच्च न्यायालय को एक सप्ताह के भीतर मामले पर सुनवाई करनी चाहिए, अपील सुननी चाहिए और तीन महीने के भीतर फैसला सुनाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि हम उच्च न्यायालय से अपील पर सुनवाई करने और तीन महीने से अधिक समय में फैसला सुनाने का अनुरोध करने के लिए इसे उपयुक्त मामला मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई सभी संबंधित अपीलों की सुनवाई साथ-साथ की जाए। सेंगर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि पूर्व विधायक अपनी सजा के लगभग 9 वर्ष और 7 महीने पूरे कर चुके हैं और उन्होंने शेष अवधि के

लिए अस्थायी रोक लगाने की मांग की। सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय को सूचित किया कि अपील की सुनवाई 11 फरवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय में होनी है और उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर विचार करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने प्रश्न उठाया कि क्या अपील हत्या की धारा के तहत दायर की जानी चाहिए थी, जबकि मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सेंगर ने वास्तव में सजा के सिर्फ सात वर्ष से अधिक ही पूरे किए हैं, और इस बात पर जोर दिया कि ऐसे गंभीर और नैतिक रूप से निंदनीय मामले में सजा में छूट देना अत्यधिक विवादास्पद है। सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश ने सेंगर के वकील महमूद प्राचा को मामले पर मीडिया में टिप्पणी करने के खिलाफ चेतावनी दी और कहा कि मामले का मीडिया ट्रायल करने पर उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता

भारत के खिलाफ तय कार्यक्रम के अनुसार मैच खेलने को राजी पाकिस्तान

नई दिल्ली । आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ी अपडेट सामने रही है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान की टीम भारत के साथ मैच खेलने के लिए तैयार है. फिलहाल मामला आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच चल रहा है. पीसीबी नए फैसले के ऐलान का तरीका ढूंढ रही है. रास्ता मिलते ही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ मंगलवार (10 फरवरी) को ऐलान कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी पीएम कल पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के साथ मिलकर इस मुद्दे पर फाइनल निर्णय

लेंगे. सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला तय समयानुसार 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. इससे पहले पीसीबी बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भारत के साथ मैच खेलने का बहिष्कार कर रही थी. मगर उन्होंने अब अपना फैसला बदलने का निर्णय ले लिया है. आधिकारिक रूप से पुष्टि होने की देरी है.

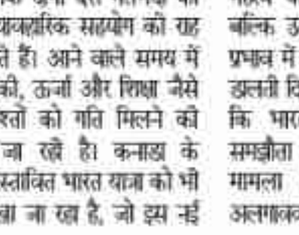

पीसीबी ने आईसीसी के सामने रखी थी कई मांगें

पीसीबी ने रविवार (आठ फरवरी) को आईसीसी के सामने कई मांगें रखीं थी. हालांकि, एनडीटीवी सूत्रों के अनुसार जय शाह के नेतृत्व वाली वैश्विक क्रिकेट संस्था ने कुछ प्रमुख प्रस्तावों को खारिज कर दिया है. जिन तीन मांगों को ठुकराया गया है. वे कुछ इस प्रकार हैं-

1- पीसीबी और बीसीबी की तरफ से पहली मांग यह थी कि भारत को पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज पर बातचीत के लिए कहा जाना चाहिए. मगर आईसीसी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. यहां तक कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल भी उनके अधीन नहीं आता है.

2- पीसीबी और बीसीबी की दूसरी मांग यह थी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच त्रिकोणीय सीरीज खेली जानी चाहिए. मगर आईसीसी ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया. बोर्ड ने कहा कि यह भी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

3- तीसरी मांग यह थी कि भारतीय टीम को इस साल सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करना चाहिए. जिसपर आईसीसी ने कहा कि यह फैसला भी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.

अजित डोभाल के दौरे से भारत-कनाडा रिश्तों में आई नई गर्माहट, दोनों देश मिलकर सिखाएंगे खालिस्तानियों को सबक

नई दिल्ली । भारत और कनाडा के रिश्तों में पिछले कुछ समय से चला आ रहा तनाव अब कम होता दिख रहा है। इस बदलाव के केंद्र में हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की हालिया कनाडा यात्रा, जिसने दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को नई दिशा दी है। यह यात्रा भरोसे की फिर से स्थापना और साझा हितों पर आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत थी। हम आपको बता दें कि अजित डोभाल ने ओटावा में कनाडा के शीर्ष सुरक्षा और नीति अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की। इन बैठकों में दोनों देशों ने एक साझा कार्य योजना पर सहमति जताई जिसका मकसद सुरक्षा और कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करना है। तय हुआ कि दोनों देश अपने सुरक्षा और कानून प्रवर्तन तंत्र के बीच सीधा संपर्क बढ़ाएंगे, लायजन अधिकारी तैनात करेंगे और सूचनाओं का तेज आदान-प्रदान सुनिश्चित करेंगे। बातचीत के प्रमुख विषयों में साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध, ड्रग तस्करी, अवैध वित्त प्रवाह, आव्रजन से जुड़ी धोखाधड़ी और ट्रांसनैशनल अपराध शामिल रहे। खास जोर इस बात पर रहा कि नई तकनीक और डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर अपराध करने वाले नेटवर्क से मिलकर निपटा जाए। कनाडा की ओर से यह भी संकेत दिया गया कि उसकी जमीन का उपयोग किसी भी तरह की हिंसक अलगाववादी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। यह बात भारत के लिए खास मायने रखती है, क्योंकि लंबे समय से भारत कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी तत्वों को लेकर चिंता जताता रहा है। गौरतलब है कि 2023 में एक खालिस्तानी उग्रवादी की हत्या के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तीखा तनाव आया था। आरोप और प्रत्यारोप चले, राजनयिक स्तर पर कड़वाहट बढ़ी और भरोसे में कमी आई। ऐसे माहौल में डोभाल की यह यात्रा एक भरोसा बहाल करने वाला कदम मानी जा रही है। अब संकेत साफ है कि दोनों देश मतभेदों को पीछे छोड़कर व्यावहारिक सहयोग की राह पर चलना चाहते हैं। आने वाले समय में व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी रिश्तों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री की प्रस्तावित भारत यात्रा को भी इसी क्रम में देखा जा रहा है, जो इस नई समझ को और मजबूती दे सकती है। देखा जाए तो अजित डोभाल की कनाडा यात्रा का महत्व केवल कागजी समझौतों में नहीं, बल्कि उसके सामरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव में है। यह यात्रा तीन स्तर पर असर डालती दिखती है। पहला, इसने साफ किया कि भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं पर समझौता करने वाला देश नहीं है। चाहे मामला साइबर खतरे का हो या अलगाववादी नेटवर्क का, भारत अब सीधे, स्पष्ट और परिणाम केंद्रित संवाद करता है। दूसरा, यह खालिस्तानी तत्वों के लिए एक सख्त संदेश है। लंबे समय तक उन्हें यह भरोसा रहा कि विदेश की जमीन पर वे राजनीतिक अभिव्यक्ति के नाम पर भारत विरोधी अभियान चला सकते हैं। पर जब मेजबान देश खुद सुरक्षा सहयोग पर सहमत हो और ऐसी गतिविधियों को कानून व्यवस्था का विषय माने, तो उनके लिए जगह सिमटती है।